

सोलर दीदी योजना : महिला सशक्तीकरण
और ग्रामीण विकास की नई किरण

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर
उत्तराखंड के विकास की नई धुरी

RNI No.: UPHIN/2018/76675

वर्ष 7 | अंक 5 | मई 2026 | ₹20

निर्माणशाला टाइम्स

हिंदी मासिक पत्रिका

गाँव से विकास की नई कहानी

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
और स्वावलंबन की ओर
बढ़ता भारत



स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम

- डिजिटल टेक्नोलॉजी से कृषि में बदलाव
- स्वास्थ्य सेवाओं की नई पहल
- शिक्षा से सशक्त होता समाज

आत्मनिर्भर भारत की ओर

विकास, रोजगार और नवाचार का संगम



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सतत् प्रगति पथ पर



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़

- विगत दो वर्षों में **1600 से अधिक** चिकित्सकीय पदों पर भर्तियां
- दूरस्थ इलाकों तक सुगम चिकित्सा सेवाओं के लिए **पीएम जनमन योजना** अंतर्गत 57 डेडीकेटेड मोबाइल मेडिकल यूनिट
- टेलीमेडिसिन के माध्यम से विगत दो वर्षों में **2 लाख से अधिक** लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 31.44 लाख से अधिक क्लेम प्रकरणों में लगभग **₹4551 करोड़** का उपचार/भुगतान
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 2273 लाभार्थियों को **₹62.20 करोड़** की उपचार सहायता
- मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष अंतर्गत विगत दो वर्षों में 177 कार्यों हेतु **₹271.45 करोड़** की प्रशासकीय स्वीकृति
- 5 नए** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- 6 नवीन** शासकीय फिजियोथैरेपी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- 9 नवीन** शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना



छत्तीसगढ़
आरोग्य जलजोष

सुशासन से समृद्धि की ओर

f X @ ChhattisgarhCMO f X DPRChhattisgarh www.dpreg.gov.in



14 | ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सम्पत्ति स्वामित्व को मजबूत करने के लिए केंद्र ने SVAMITVA योजना पर दिया जोर



नारी शक्ति वंदन सम्मेलन
महिला सशक्तिकरण को मिला नया आयाम



12 महिलाओं के सशक्तिकरण पर झारखण्ड की उपलब्धियों को मिला वैश्विक मंच



16 बेटियों के सशक्तिकरण की मजबूत पहल : मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना



22 श्रमिक सशक्तिकरण की नई उड़ान: विकास, सम्मान और सुविधाओं की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

निर्माणशाला टाइम्स

हिंदी मासिक पत्रिका

मूल्य: 20 रुपये, मई 2026

वर्ष-7 अंक: 05, पृष्ठ: 52

प्रधान संपादक

मनोज कुमार सिंह

संपादक

अहमद हसन

सह संपादक

दिव्यांश मिश्रा

Website: www.nirmanshalatimes.com

E-mail: nirmanshalatimes@gmail.com

Mob: +919540284632

ब्यूरो प्रमुख

उत्तराखंड-
उत्तर प्रदेश-
दिल्ली-
बिहार-
हरियाणा-
झारखंड-
डिजाइन-

विनय त्रिवाल
लल्लन कुमार मिश्रा
दिनेश कुमार सिंह
सैयद मोहम्मद अली
संतोष कुमार सिंह
परवेज कमाल
चंद्रजीत कुमार

विज्ञापन, प्रसार संपर्क और पत्र व्यवहार

NST MEDIA

WP-02, Block 'C'

Sector - 71, Noida - 201301

Distt. Gautam Buddha Nagar (UP)

कार्यालय

मुद्रक, प्रकाशक एवं स्वामी
सैयद नौशाद मंजर,
मुद्रित- नीलू प्रिंटिंग प्रेस, E-33,
सेक्टर-7, नोएडा, उत्तर प्रदेश से,
प्रकाशित- टी-1,
श्री जी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-5,
नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश से,
संपादक- अहमद हसन।

पत्र का नाम-

निर्माणशाला टाइम्स

(Nirmanshala Times)

RNI NO- UPHIN/2018/76675



संपादकीय

विकास की नई दिशा

भारत सरकार ने हाल के वर्षों में औद्योगिक, अवसंरचनात्मक (इंफ्रास्ट्रक्चर) और कृषि क्षेत्रों में कई ऐसे निर्णायक कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना भी है। एक संपादकीय दृष्टि से देखें तो ये प्रयास देश की आर्थिक संरचना को अधिक समावेशी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की “मेक इन इंडिया” और “प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI)” जैसी योजनाओं ने विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को नई गति दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है, जिससे न केवल बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं बल्कि उनसे जुड़े छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को भी बढ़ावा मिला है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार सृजित होने की संभावना बनी है। साथ ही, स्टार्टअप इंडिया अभियान ने युवाओं को नवाचार आधारित स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में “गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान”, “भारतमाला परियोजना” और “सागरमाला” जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क, रेल, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। ये परियोजनाएं न केवल देश के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ रही हैं बल्कि निर्माण कार्यों के दौरान बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और उद्योग को गति मिलती है, जिससे दीर्घकालिक रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं।

कृषि क्षेत्र में सरकार ने “प्रधानमंत्री किसान

सम्मान निधि (PM-KISAN)”, “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” और “कृषि अवसंरचना कोष” जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम को कम करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही, कृषि को तकनीक और बाजार से जोड़ने की दिशा में ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया है। इससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ी है और कृषि आधारित उद्योगों—जैसे खाद्य प्रसंस्करण—में स्वरोजगार के नए रास्ते खुले हैं।

इन तीनों क्षेत्रों में हो रहे विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये एक-दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों को गति देता है, उद्योग कृषि उत्पादों के लिए बाजार तैयार करते हैं और कृषि क्षेत्र की समृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। इस समग्र दृष्टिकोण से देश के आम नागरिक, विशेषकर युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

हालांकि, इन प्रयासों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना प्रभावी और पारदर्शी होता है। कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) और वित्तीय पहुंच (फाइनेंस एक्सेस) को और मजबूत करने की आवश्यकता बनी हुई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन अवसरों का लाभ उठा सकें।

निष्कर्षतः, सरकार के इन बहुआयामी प्रयासों ने एक सकारात्मक दिशा तो दिखाई है, लेकिन यह आवश्यक है कि नीति और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को लगातार कम किया जाए। तभी औद्योगिक विकास, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और समृद्ध कृषि के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक तक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर वास्तविक रूप में पहुंच पाएंगे।



सोलर दीदी योजना महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास की नई किरण

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित “सोलर दीदी” योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण और सतत विकास की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में उभर रही है। इस योजना के माध्यम से गांवों की महिलाओं को सौर ऊर्जा से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत महिलाओं को सोलर लैंप, सोलर पैनल, चार्जिंग यूनिट तथा अन्य सौर उपकरणों की स्थापना, संचालन और रखरखाव की विस्तृत जानकारी दी जाती है। साथ ही, तकनीकी खराबियों के समाधान और सोलर उत्पादों के विपणन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इससे महिलाएं न केवल तकनीकी रूप से दक्ष बन रही हैं, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका भी निभा रही हैं।

“सोलर दीदी” योजना न केवल गांवों में उजाला फैला रही है, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाकर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की एक नई मिसाल भी स्थापित कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली आपूर्ति लंबे समय से एक चुनौती रही है, वहां “सोलर दीदी” अब भरोसेमंद ऊर्जा समाधान के रूप में सामने आई हैं। वे गांव-गांव में सौर उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही हैं और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान भी कर रही हैं।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण है। सोलर

उत्पादों की बिक्री और सेवाओं के माध्यम से महिलाएं नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इससे न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।

इसके अतिरिक्त, “सोलर दीदी” जागरूकता अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे ग्रामीण समुदाय को सौर ऊर्जा के लाभों के बारे में जानकारी देकर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत के प्रयासों को भी गति दे रही है।

सरकार और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से यह योजना निरंतर विस्तार की ओर अग्रसर है। भविष्य में अधिक से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रत्येक गांव ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। ■



दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर उत्तराखंड के विकास की नई धुरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ उत्तराखंड के विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। यह परियोजना केवल एक परिवहन संपर्क मार्ग नहीं, बल्कि रोजगार, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला एक समग्र “ग्रीन कॉरिडोर” है, जिसकी परिकल्पना पर्वतीय राज्य की आर्थिक क्षमता को राष्ट्रीय मुख्यधारा से गहराई से जोड़ने के उद्देश्य से की गई है।

इस कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय घटकर लगभग

ढाई घंटे रह जाने की संभावना है। तेज और सुगम कनेक्टिविटी का यह बदलाव न केवल आम यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। चारधाम यात्रा, जिम कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, मसूरी, टिहरी झील जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच अब अधिक सरल और समयबद्ध होगी, जिससे पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका आर्थिक और कृषि आधारित प्रभाव माना जा रहा है। पहाड़ों में उत्पादित स्थानीय फसलें

और हस्तनिर्मित उत्पाद—जैसे हर्षिल के सेब, जोशीमठ और चकराता की राजमा, पुरोला का लाल चावल तथा रुद्रप्रयाग का बुरांश जूस—अब बड़े बाजारों तक तेजी से और कम लागत में पहुंच सकेंगे। इससे न केवल लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, बल्कि किसानों और उत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य भी प्राप्त होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कॉरिडोर राज्य में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग और एग्री-लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नए निवेश को आकर्षित करेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को भी नई दिशा मिलेगी। लंबे समय से उत्तराखंड में जारी पलायन की समस्या को कम करने की दिशा में यह परियोजना एक प्रभावी कदम के रूप में देखी जा रही है।

पर्यटन और कृषि के साथ-साथ यह कॉरिडोर स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक उत्पादों को भी व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में सहायक होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की यह पहल न केवल आजीविका के नए साधन विकसित करेगी, बल्कि क्षेत्रीय संतुलित विकास की अवधारणा को भी मजबूती प्रदान करेगी।

हालांकि, इस प्रकार की विशाल अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के साथ पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास की चुनौतियाँ भी जुड़ी होती हैं। इसलिए विशेषज्ञ यह भी सुझाव दे रहे हैं कि विकास के साथ-साथ पारिस्थितिकी संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि “ग्रीन कॉरिडोर” की अवधारणा केवल नाम तक सीमित न रह जाए, बल्कि वास्तव में एक संतुलित और टिकाऊ मॉडल के रूप में स्थापित हो।

कुल मिलाकर, दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर उत्तराखंड के लिए केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्गठन और सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने की क्षमता रखता है। यदि यह परियोजना अपने उद्देश्यों के अनुरूप आगे बढ़ती है, तो यह आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की विकास यात्रा को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। ■



युवाओं को स्वरोजगार की राह सीएम युवा योजना में क्रेडिट काउंसलर्स की नई पहल

प्र देश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने सीएम युवा योजना को और गति देने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स (CCC) की विशेष ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और आसान ऋण उपलब्धता से जोड़ना है।

गोमतीनगर में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 50 जिलों और दूसरे चरण में 25 जिलों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कुल 90 सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात किए जाएंगे, जो युवाओं को बैंकिंग प्रक्रियाओं, दस्तावेजीकरण और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग देंगे।

एमएसएमई और बैंकों के बीच मजबूत कड़ी

यूपीकॉन के प्रबंध निदेशक प्रवीण सिंह के अनुसार, ये काउंसलर्स एमएसएमई उद्यमियों और बैंकों के बीच सेतु का कार्य करेंगे। वे न केवल उपयुक्त ऋण योजनाओं की जानकारी देंगे, बल्कि क्रेडिट रेटिंग, सिबिल स्कोर और वित्तीय योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिससे युवाओं के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो सके।



1.5 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य

सरकार ने इस वर्ष सीएम युवा योजना के तहत 1.5 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पहल युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तीकरण को भी नई दिशा देगी।

राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के सहयोग से संचालित किया जा रहा है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है। CCC कोर्स को विशेष रूप से इस तरह तैयार किया गया है कि

काउंसलर्स युवाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

रोजगार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा

यह पहल न केवल युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेगी, बल्कि सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों और अनुभवी पेशेवरों को भी अपनी विशेषज्ञता साझा करने का अवसर प्रदान करेगी। इससे प्रदेश में वित्तीय समावेशन को मजबूती मिलने के साथ-साथ एमएसएमई सेक्टर को भी नया आधार मिलेगा।

कुल मिलाकर, सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर्स की यह पहल प्रदेश में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करने की ओर अग्रसर है। ■

नारी शक्ति वंदन सम्मेलन महिला सशक्तिकरण को मिला नया आयाम



रा

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतकारी कदम बताया। इस अधिनियम के अंतर्गत

लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में शक्ति के बिना सृजन की कल्पना अधूरी है, इसलिए नारी शक्ति के बिना राष्ट्र की वास्तविक उन्नति संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं की विविध भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि आज की नारी किसान, उद्यमी, जनप्रतिनिधि और नेतृत्वकर्ता— सभी रूपों में देश के विकास में समान रूप से योगदान दे रही है।

उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मातृत्व वंदना योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों ने



महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा दी है।

राज्य सरकार की पहलें

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार भी महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सशक्त बहना उत्सव योजना तथा मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूहों के उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही हाउस ऑफ हिमालयाज अम्ब्रेला ब्रांड के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में 2 लाख 65 हजार से अधिक “लखपति दीदियाँ” अब वार्षिक एक लाख रुपये से अधिक आय अर्जित कर रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है तथा समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के

अधिकारों और सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है।

महिलाओं की भूमिका पर विशेष बल

कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के भविष्य को दिशा देने वाला परिवर्तनकारी कदम है, जिससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और अधिक सशक्त होगी।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि यह कानून महिलाओं को केवल प्रतिनिधित्व ही नहीं देता, बल्कि उन्हें निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं अनुभव और नेतृत्व क्षमता के आधार पर समाज को नई दिशा दे रही हैं।

कार्यक्रम में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना, पद्मश्री श्रीमती माधुरी बर्थवाल सहित अनेक विशिष्टजन एवं बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। ■



उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नई गति **कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिल रही ऐतिहासिक रफ्तार**

उ

त्तराखंड राज्य में
आधारभूत ढांचे के
क्षेत्र में पिछले कुछ
वर्षों में जो परिवर्तन

दिखाई दे रहा है, वह अब ठोस
परिणामों के रूप में सामने आने
लगा है। सड़क, रेल और
कनेक्टिविटी से जुड़ी बहुप्रतीक्षित
परियोजनाएँ एक नए चरण में प्रवेश
कर चुकी हैं, जिससे राज्य के
पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के बीच
दूरी न केवल भौगोलिक रूप से
घट रही है, बल्कि आर्थिक और
सामाजिक रूप से भी नए अवसरों
का द्वार खुल रहा है।



हाल ही में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद राजधानी से दिल्ली की यात्रा का समय घटकर ढाई घंटे रह जाना, इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। शुरुआती दिनों में इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के अनुभवों को सकारात्मक बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आधुनिक सड़क अवसंरचना आमजन के जीवन में प्रत्यक्ष सुविधा और भरोसा लेकर आई है।

राज्य सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न इंफ्रा परियोजनाएँ वर्तमान में प्रगति पर हैं। आने वाले एक वर्ष को इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है,

उत्तराखंड आज एक ऐसे परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यटन विस्तार का मजबूत आधार बनता दिखाई दे रहा है। आने वाला एक वर्ष राज्य के विकास इतिहास में एक निर्णायक अध्याय जोड़ने की क्षमता रखता है।

क्योंकि कई प्रमुख योजनाएँ पूर्णता के अंतिम चरण में हैं।

इनमें पौटा साहिब-देहरादून चार लेन मार्ग, जिसकी लागत लगभग 1650 करोड़ रुपये है, अगले माह तक यातायात के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। इसी प्रकार सहारनपुर बाईपास से हरिद्वार तक 51 किलोमीटर लंबा छह लेन हाईवे जून तक चालू किए जाने की योजना है। हरिद्वार बाईपास परियोजना का प्रथम चरण भी आगामी कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

कुंभ क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से ऋषिकेश बाईपास परियोजना पर भी कार्य गति पकड़ रहा है, जिसके अगस्त तक प्रारंभ होने की संभावना है। वहीं झांझरा-आशारोड एलिवेटेड रोड परियोजना, जो 716 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही है, अगले वर्ष अप्रैल तक पूर्ण होने की उम्मीद है।

कुमाऊं क्षेत्र में भी विकास कार्य समान रूप से तेजी पकड़ रहे हैं। रुद्रपुर फोरलेन बाईपास और काशीपुर बाईपास जैसी परियोजनाएँ क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर तक पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर हैं, जिससे शहरी यातायात दबाव में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त टनकपुर-पिथौरागढ़-लिपुलेख मार्ग जैसी रणनीतिक और सीमांत क्षेत्र की परियोजनाएँ अगले एक वर्ष में पूर्ण होने की उम्मीद के साथ राज्य की कनेक्टिविटी को नया आयाम दे रही हैं। राज्य के विकास मॉडल को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त “आधुनिक सड़कें किसी राज्य की भाग्य रेखा होती हैं” जैसी अवधारणा को आधार बनाते हुए राज्य सरकार भी अवसंरचना विस्तार पर विशेष बल दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगले एक वर्ष में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ पूरी होकर राज्य की कनेक्टिविटी, पर्यटन और तीर्थाटन को अभूतपूर्व गति प्रदान करेंगी।

इसके साथ ही कर्णप्रयाग रेललाइन के प्रथम चरण को वर्ष के अंत तक लोकार्पित करने के प्रयास भी तेज हैं, जो पर्वतीय राज्य के लिए रेल संपर्क के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो सकती है। ■



कल्पना सोरेन को 'वुमेन एम्पावरमेंट
ट्रेलब्लेज़र्स अवार्ड' से सम्मानित –

महिलाओं के सशक्तिकरण पर झारखण्ड की उपलब्धियों को मिला वैश्विक मंच

न

ई दिल्ली के प्रतिष्ठित हयात रीजेंसी में आयोजित 'BRICS CCI WE एनुअल वुमेन समिट एंड फेलिसिटेशन 2026' के दौरान

झारखण्ड के गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 'वुमेन एम्पायरमेंट ट्रेलब्लेज़र्स अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह

सम्मान ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महिला सशक्तिकरण विंग की ओर से प्रदान किया गया। समारोह में देश-विदेश के नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और



सामाजिक क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। यह आयोजन महिलाओं के नेतृत्व, उद्यमिता और सामाजिक-आर्थिक भागीदारी को वैश्विक स्तर पर सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया।

“यह सम्मान हर महिला के संघर्ष और सपनों का प्रतीक है” — कल्पना सोरेन

पुरस्कार ग्रहण करते हुए कल्पना सोरेन ने इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि न मानते हुए झारखण्ड और देशभर की उन महिलाओं को समर्पित किया जो अपने परिश्रम, साहस और संकल्प के बल पर परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं केवल विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी ही नहीं कर रही, बल्कि नेतृत्व करते हुए विकास की दिशा भी तय कर रही हैं।

उन्होंने अपने संबोधन में विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि उद्यमी और परिवर्तन की अग्रदूत के रूप में देखा जाना चाहिए।

झारखण्ड मॉडल पर जोर, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को सराहा

कल्पना सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है।

वैश्विक अनुभव और समावेशी सशक्तिकरण की आवश्यकता

उन्होंने अपने हालिया अंतरराष्ट्रीय अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताया कि ऑक्सफोर्ड जैसे वैश्विक संस्थानों में अध्ययनरत झारखण्ड की छात्राओं का जुझारूपन और दृढ़ता प्रेरणादायक



यह सम्मान न केवल कल्पना सोरेन के सार्वजनिक जीवन में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की मान्यता है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि झारखण्ड जैसे राज्यों में जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव अब राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं।

बल्कि उसमें निष्पक्ष अवसर और वास्तविक समानता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति

इस अवसर पर पूर्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, एनआईसी के महानिदेशक एवं अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह, पूर्व BRICS शेरपा संजय भट्टाचार्य, कोयला मंत्रालय की संयुक्त सचिव डॉ. रूपिंदर बरार, अभिनेत्री शबाना आज़मी, यूएन एडवोकेट एवं अभिनेत्री भूमि पेडनेकर सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। साथ ही BRICS CCI महिला विंग की अध्यक्ष लेबोर्गैंग जुलु तथा अन्य वैश्विक प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। ■

है। उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया केवल समावेशन तक सीमित नहीं होनी चाहिए,

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और **सम्पत्ति स्वामित्व** को मजबूत करने के लिए **केंद्र ने SVAMITVA** **योजना** पर दिया जोर



भारत की एक बड़ी आबादी गांवों में निवास करती है, जहां संपत्ति के अधिकार अक्सर पारंपरिक और अनौपचारिक व्यवस्थाओं पर आधारित होते हैं। इससे न केवल विवाद उत्पन्न होते हैं बल्कि ग्रामीण नागरिकों को बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने में भी कठिनाई होती है। SVAMITVA योजना इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है और ग्रामीण विकास को नई दिशा देती है।

इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों का सटीक सर्वेक्षण किया जाता है, जिससे प्रत्येक संपत्ति का स्पष्ट सीमांकन संभव हो पाता है। इसके बाद संपत्ति मालिकों को “प्रॉपर्टी कार्ड” प्रदान किया जाता है, जो उनके स्वामित्व का आधिकारिक प्रमाण होता है। यह कार्ड न केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि इसे बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के समक्ष संपत्ति के रूप में प्रस्तुत कर ऋण प्राप्त करने में भी उपयोग किया जा सकता है।

SVAMITVA योजना का एक प्रमुख सकारात्मक पहलू यह है कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देती है। जब ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति को औपचारिक रूप से गिरवी रखकर ऋण ले सकते हैं, तो वे कृषि, लघु उद्योग, स्वरोजगार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में निवेश कर सकते हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण होता है।



ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट एवं सुरक्षित करने की दिशा में केंद्र सरकार की SVAMITVA योजना (Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas) एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल के रूप में उभरकर सामने आई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण कर उन्हें डिजिटल रूप से मानचित्रित करना और ग्रामीण निवासियों को उनकी संपत्ति का वैध स्वामित्व दस्तावेज़ प्रदान करना है।



इसके अलावा, यह योजना संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने में भी सहायक है। स्पष्ट सीमांकन और आधिकारिक रिकॉर्ड होने से पड़ोसियों के बीच होने वाले झगड़े और कानूनी विवादों में कमी आती है। इससे सामाजिक सद्भाव और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है।

डिजिटल इंडिया अभियान के तहत SVAMITVA योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मैपिंग और ऑनलाइन रिकॉर्ड प्रबंधन जैसी प्रक्रियाएं ग्रामीण प्रशासन को आधुनिक बनाती हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से भी यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर या संयुक्त रूप से दर्ज किया जाता है, तो यह उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाता

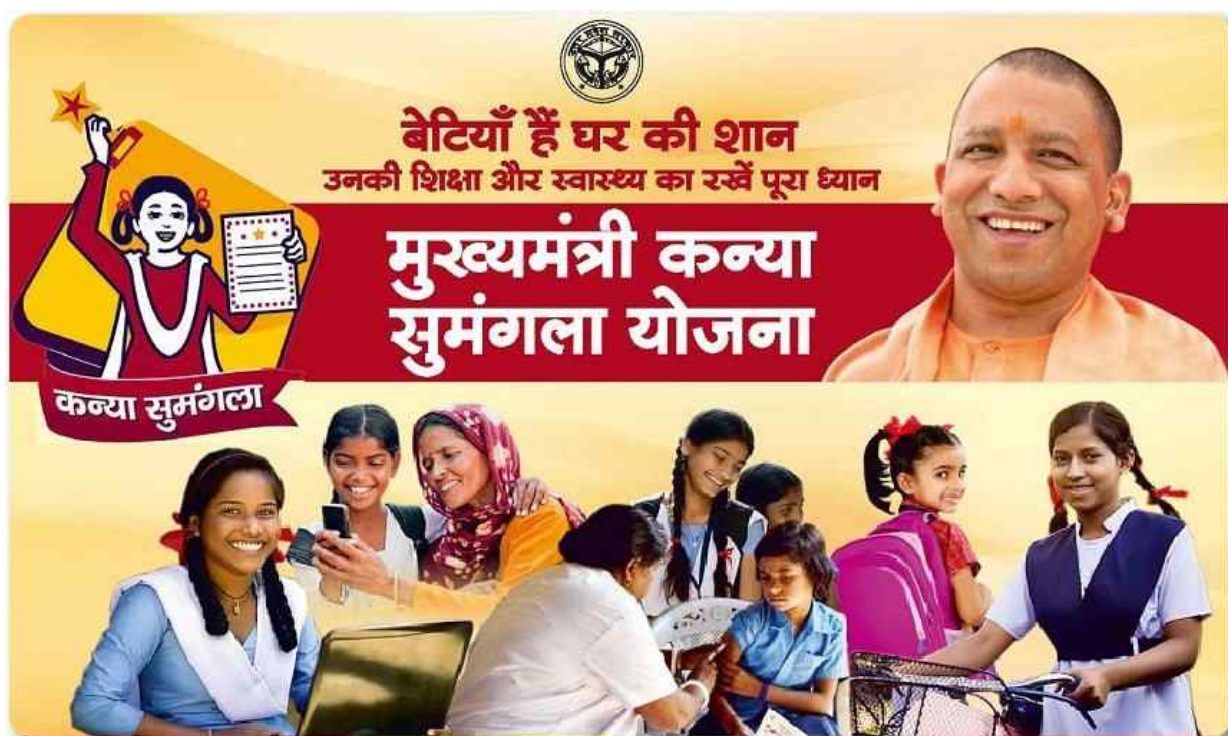
SVAMITVA योजना एक बहुआयामी पहल है, जो ग्रामीण भारत की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना न केवल संपत्ति के स्वामित्व को सुनिश्चित करती है, बल्कि ग्रामीण नागरिकों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। यदि इसका प्रभावी और व्यापक क्रियान्वयन जारी रहता है, तो यह आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकती है।

है। इससे लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलता है।

SVAMITVA योजना स्थानीय प्रशासन के लिए भी लाभकारी सिद्ध होती है। ग्राम पंचायतों को संपत्ति का सटीक रिकॉर्ड मिलने से वे बेहतर योजना बना सकते हैं और कर संग्रह (property tax) में भी सुधार होता है। इससे पंचायतों की आय बढ़ती है और वे गांव के विकास कार्यों में अधिक निवेश कर पाती हैं।

यह योजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करती है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, तो देश की समग्र अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। SVAMITVA योजना ग्रामीण भारत को केवल संपत्ति अधिकार ही नहीं देती, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करने का माध्यम भी बनती है।

बेटियों के सशक्तिकरण की मजबूत पहल मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना



यो

गी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आज बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की एक सशक्त नींव बन चुकी है।

वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करें।

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना ने

अब तक 27 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया है। करीब 674 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है, जो इसकी पारदर्शिता और प्रभावशीलता को दर्शाती है।

आर्थिक सुरक्षा के साथ शिक्षा को बढ़ावा

यह योजना बालिकाओं को छह चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है—जन्म से लेकर स्नातक स्तर



मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आज इस बात का प्रमाण है कि सही नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन से बेटियों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बनाया जा सकता है।

तक। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग देना ही नहीं, बल्कि बालिकाओं की शिक्षा को निरंतर बनाए रखना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।

- जन्म पर 5000
- पूर्ण टीकाकरण के बाद 2000
- कक्षा 1 में प्रवेश पर 3000
- कक्षा 6 में प्रवेश पर 3000
- कक्षा 9 में प्रवेश पर 5000
- उच्च शिक्षा (स्नातक/डिप्लोमा) में प्रवेश पर 7000

इस प्रकार कुल 25,000 की सहायता बालिका के भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करती है।

समाज में सकारात्मक सोच का निर्माण

यह योजना बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ अभियान को मजबूती देती है। इसके माध्यम से लिंगानुपात में सुधार, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक और बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। यह केवल आर्थिक योजना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बन चुकी है।

पारदर्शिता और सुगम प्रक्रिया

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनाई गई है। पीएफएमएस प्रणाली के जरिए धनराशि सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना समाप्त हो जाती है।

पात्रता और विशेष प्रावधान

योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों और जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इसका लाभ दिया जाता है। हालांकि, जुड़वा बालिकाओं या गोद ली गई बच्चियों के मामलों में विशेष छूट भी प्रदान की गई है।

सशक्त भविष्य की ओर कदम

महिला कल्याण निदेशालय की पहल से यह योजना लाखों परिवारों के लिए आशा की किरण बनी है। यह न केवल बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि समाज में उनके प्रति सम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित कर रही है। ■

उज्ज्वला के 10 साल ग्रामीण महिलाओं का जीवन बदलने वाली योजना



भा

रत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ग्रामीण जीवन लंबे समय तक कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा है। विशेषकर रसोई से जुड़ी समस्याएं—धुएँ से भरे चूल्हे, लकड़ी या गोबर के उपले इकट्ठा करने की मेहनत, और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं—ग्रामीण महिलाओं के जीवन का एक सामान्य हिस्सा थीं। ऐसे परिदृश्य में “उज्ज्वला योजना” ने एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत की। पिछले 10 वर्षों में इस योजना ने न केवल रसोई के तौर-तरीकों को बदला है, बल्कि महिलाओं के जीवन में गरिमा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण का नया अध्याय जोड़ा है।

स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में बड़ा कदम

पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाला धुआँ महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा था। आँखों में जलन, सांस की बीमारियाँ और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं आम थीं। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिलने से इन समस्याओं में उल्लेखनीय कमी आई है। स्वच्छ ईंधन के उपयोग ने महिलाओं को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान किया है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

समय और श्रम की बचत

पहले ग्रामीण महिलाओं को ईंधन के लिए घंटों जंगलों या खेतों में भटकना पड़ता था। यह समय और ऊर्जा दोनों की भारी बर्बादी थी। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने से यह मेहनत कम हो गई है। अब महिलाएं उस समय का उपयोग अन्य उत्पादक कार्यों में कर पा रही हैं—जैसे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना,

उज्ज्वला योजना के 10 वर्षों का सफर भारत के ग्रामीण विकास की एक प्रेरणादायक कहानी है। इसने महिलाओं के जीवन में स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया उजाला लाया है। यह योजना केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। आने वाले समय में, यदि इसे और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह लाखों और परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस प्रकार, उज्ज्वला योजना ने यह सिद्ध कर दिया है कि सही दिशा में उठाया गया एक कदम समाज के हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है।

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ना या छोटे व्यवसाय शुरू करना।

महिला सशक्तिकरण की नई पहचान

उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को केवल एक सुविधा नहीं दी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान किया है। गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर जारी किए जाने से उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है। यह कदम महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

पर्यावरण संरक्षण में योगदान

लकड़ी और अन्य ठोस ईंधनों के उपयोग से

न केवल स्वास्थ्य पर असर पड़ता था, बल्कि वनों की कटाई और पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता था। एलपीजी के उपयोग से इन समस्याओं में कमी आई है। इससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला बल

उज्ज्वला योजना ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया है। गैस एजेंसियों, डिलीवरी सेवाओं और संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा, महिलाओं द्वारा बचाए गए समय का उपयोग आर्थिक गतिविधियों में होने से परिवार की आय में भी वृद्धि हुई है।

सामाजिक बदलाव की नींव

यह योजना केवल रसोई तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने सामाजिक सोच को भी प्रभावित किया है। स्वच्छ ईंधन के प्रति जागरूकता बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक जीवनशैली को अपनाने की प्रवृत्ति मजबूत हुई है। महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधा को प्राथमिकता देने की सोच भी विकसित हुई है।

चुनौतियाँ और आगे की राह

हालांकि उज्ज्वला योजना ने कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं। गैस सिलेंडर की कीमत और रीफिल की लागत कई परिवारों के लिए अभी भी चिंता का विषय है। इसके समाधान के लिए सब्सिडी और जागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। साथ ही, निरंतर निगरानी और सुधार के जरिए इस योजना को और मजबूत किया जा सकता है। ■



केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं समावेशी विकास की सशक्त आधारशिला

भा रत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जनकल्याणकारी योजनाएं केवल नीतियां नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित ये योजनाएं समाज के हर वर्ग—किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और उद्यमियों—को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार ने अनेक प्रभावी पहल की हैं। **आयुष्मान भारत योजना** के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुई हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम हुआ है। वहीं **प्रधानमंत्री आवास योजना** ने लाखों लोगों को पक्के घर का सपना पूरा करने का अवसर दिया है, जो सम्मानजनक जीवन की ओर एक बड़ा कदम है।

कृषि क्षेत्र में **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)** जैसी योजनाओं ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आय को स्थिर बनाने में मदद की है। इसके साथ ही सिंचाई, बीमा और आधुनिक उपकरणों

केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं एक ऐसे भारत की नींव रख रही हैं, जहां विकास समावेशी, संतुलित और सतत हो। ये योजनाएं केवल सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और बेहतर भविष्य की दिशा में प्रेरणा हैं—एक ऐसा भविष्य, जहां हर नागरिक को समान अवसर और प्रगति का अधिकार प्राप्त हो।

की उपलब्धता ने खेती को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाया है।

रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं को नए अवसर दिए हैं। इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे युवा अपने व्यवसाय की शुरुआत कर आत्मनिर्भर बन रहे

हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी कई योजनाएं प्रभावी साबित हो रही हैं। स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) और विभिन्न वित्तीय योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं और परिवार व समाज में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। इसी प्रकार, शिक्षा क्षेत्र में छात्रवृत्ति योजनाएं और डिजिटल शिक्षा पहल ने बच्चों और युवाओं के भविष्य को नई दिशा दी है।

राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं लागू कर रही हैं, जिससे विकास का लाभ हर क्षेत्र तक पहुंच रहा है। चाहे वह मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं हों, किसानों के लिए विशेष पैकेज या युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम—हर राज्य अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समाज के विकास में योगदान दे रहा है।

इन योजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें पारदर्शिता और डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है और विश्वास बढ़ा है। ■

भारत में डिजिटल सुधारों से MSME की उत्पादकता में वृद्धि: एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्य



हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि भारत में किए गए डिजिटल सुधारों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की उत्पादकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। यह निष्कर्ष न केवल भारत की आर्थिक दिशा को मजबूत करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि तकनीकी नवाचार और नीति सुधार किस प्रकार जमीनी स्तर पर व्यवसायों को सशक्त बना सकते हैं।

भारत में MSME क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यह न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, बल्कि निर्यात, नवाचार और क्षेत्रीय संतुलित विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे में, डिजिटल सुधारों के माध्यम से इस क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि एक अत्यंत सकारात्मक संकेत है।

डिजिटल सुधारों की भूमिका

पिछले एक दशक में भारत सरकार ने

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। “डिजिटल इंडिया” पहल के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और डेटा एक्सेस को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया। इसका सीधा लाभ MSME क्षेत्र को मिला।

डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ने छोटे व्यापारियों को नकद लेन-देन की निर्भरता से मुक्त किया। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी, बल्कि लेन-देन की गति भी तेज हुई। MSME अब आसानी से अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी की स्थिति मजबूत हुई है।

औपचारिककरण और वित्तीय समावेशन

डिजिटल सुधारों का एक बड़ा प्रभाव MSME के औपचारिककरण में देखने को मिला है। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के लागू होने के बाद व्यवसायों को अपने लेन-देन का रिकॉर्ड

डिजिटल रूप में रखना पड़ा, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होने का अवसर मिला।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। पहले जहां छोटे उद्यमों को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, वहीं अब डिजिटल डेटा (जैसे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री) के आधार पर उन्हें आसानी से लोन मिल रहा है। इससे उनके विस्तार और निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं।

उत्पादकता में वृद्धि के कारक

IMF की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल सुधारों ने MSME की उत्पादकता बढ़ाने में कई तरीकों से योगदान दिया है:

1. ऑपरेशनल दक्षता में सुधार — डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर के उपयोग से उत्पादन प्रक्रियाएं अधिक सुव्यवस्थित हुई हैं।

2. बाजार तक पहुंच — ई-कॉमर्स



IMF की रिपोर्ट भारत के डिजिटल परिवर्तन की सफलता को रेखांकित करती है। MSME क्षेत्र में उत्पादकता की वृद्धि यह दर्शाती है कि सही नीतियां और तकनीकी निवेश किस प्रकार आर्थिक विकास को गति दे सकते हैं। डिजिटल सुधारों ने न केवल MSME को सशक्त बनाया है, बल्कि उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार किया है। आने वाले वर्षों में यदि इन सुधारों को और मजबूती दी जाती है, तो MSME क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार, डिजिटल इंडिया की दिशा में उठाए गए कदम न केवल वर्तमान को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार कर रहे हैं।

प्लेटफॉर्म ने छोटे व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने का अवसर दिया।

3.लागत में कमी – डिजिटल माध्यमों से मार्केटिंग, सप्लाय चैन और भुगतान प्रक्रियाएं सस्ती और तेज हुई हैं।

4.डेटा आधारित निर्णय – डिजिटल रिकॉर्ड्स के माध्यम से MSME अब बेहतर व्यावसायिक निर्णय ले पा रहे हैं।

नवाचार और प्रतिस्पर्धा

डिजिटल सुधारों ने MSME क्षेत्र में नवाचार को भी प्रोत्साहित किया है। अब छोटे उद्यम भी नई तकनीकों जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर रहे हैं। इससे वे बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हुए हैं। इसके अलावा, स्टार्टअप संस्कृति के विकास ने MSME को नई दिशा दी है। कई स्टार्टअप्स

MSME के लिए समाधान विकसित कर रहे हैं, जैसे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सप्लाय चैन मैनेजमेंट टूल्स और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर प्रभाव

डिजिटल सुधारों का प्रभाव केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी MSME तेजी से डिजिटल हो रहे हैं। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और स्मार्टफोन के प्रसार ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा है। इससे स्थानीय उद्यमों को अपने उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचने का अवसर मिला है। उदाहरण के लिए, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उत्पाद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश-विदेश में पहुंच रहे हैं।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा

डिजिटल सुधारों ने महिला उद्यमियों के

लिए भी नए अवसर पैदा किए हैं। घर से संचालित व्यवसाय अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से चलाए जा सकते हैं। डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया मार्केटिंग ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है।

चुनौतियां और आगे का रास्ता

हालांकि डिजिटल सुधारों के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा के जोखिम और इंटरनेट कनेक्टिविटी की असमानता जैसी समस्याओं पर अभी और काम करने की आवश्यकता है।

सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर MSME के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। इससे डिजिटल सुधारों का लाभ और व्यापक रूप से फैल सकेगा। ■

श्रमिक सशक्तिकरण की नई उड़ान विकास, सम्मान और सुविधाओं की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए हालिया कदम न केवल विकास की नई कहानी लिखते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी प्रगति के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता भी दर्शाते हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा 'श्रमवीर गौरव समारोह 2026' के अवसर पर की गई घोषणाएं और परियोजनाओं का शिलान्यास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में श्रमिकों को समर्पित कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें ग्रेटर नोएडा में श्रमिक सुविधा केंद्रों की स्थापना, ईएसआईसी अस्पताल के लिए भूमि आवंटन और जेवर में एक आधुनिक विद्यालय का निर्माण शामिल है। ये पहलें न केवल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगी, बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच भी प्रदान करेंगी।

ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों का उद्देश्य श्रमिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना है। अक्सर श्रमिकों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए अलग-अलग स्थानों पर भटकना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों की हानि होती है। इन केंद्रों के निर्माण से यह समस्या काफी हद तक हल होगी और श्रमिकों को एक संगठित और सुविधाजनक प्रणाली का लाभ मिलेगा। यह पहल श्रमिकों के जीवन को

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम न केवल वर्तमान में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये पहलें उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

सरल और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी क्रम में, Employees' State Insurance Corporation (ईएसआईसी) के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में 300 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित करने की योजना भी अत्यंत सराहनीय है। 7.2 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह अस्पताल श्रमिकों और उनके परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता किसी भी समाज के विकास का प्रमुख आधार होती है, और यह पहल इस दिशा में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इससे न केवल श्रमिकों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल

की है। जेवर में प्रस्तावित सीएम कंपोजिट विद्यालय का निर्माण क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सामाजिक विकास की कुंजी है। इस विद्यालय के माध्यम से बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ एक बेहतर शैक्षिक वातावरण मिलेगा, जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।

कार्यक्रम का एक अत्यंत प्रेरणादायक पहलू रहा 'प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान'। अटल आवासीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करना इस बात का प्रतीक है कि सरकार न केवल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है, बल्कि प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रयागराज और वाराणसी के अटल आवासीय विद्यालयों द्वारा सीबीएसई 10वीं में 100% परिणाम हासिल करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह न केवल विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम है, बल्कि शिक्षकों और संस्थान की गुणवत्ता का भी प्रमाण है। मेधावी छात्रों को टैबलेट प्रदान करना डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आज के समय में तकनीकी ज्ञान और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच अत्यंत आवश्यक हो गई है। टैबलेट जैसे उपकरण छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने में मदद करेंगे और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। इसके साथ ही, श्रमिकों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह पहल समाज में श्रमिकों के महत्व को रेखांकित करती है। मुन्नालाल, पंचम, आकाश, प्यारी और सरस्वती जैसे श्रमिकों को प्रमाण पत्र और टूलकिट प्रदान करना न केवल उनके मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि अन्य श्रमिकों को भी प्रेरित करता है कि उनका परिश्रम समाज द्वारा सराहा जाता है।

समग्र रूप से देखा जाए तो यह कार्यक्रम और इसमें घोषित योजनाएं उत्तर प्रदेश में समावेशी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम हैं। श्रमिकों के लिए बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा के अवसरों में वृद्धि और प्रतिभाओं का सम्मान—ये सभी पहलें एक सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगी। ■

उद्योग से खेत तक प्रगति की मजबूत नींव

भारत की विकास यात्रा में उद्योग और कृषि दो ऐसे आधार स्तंभ हैं, जो मिलकर देश की आर्थिक मजबूती और सामाजिक संतुलन को दिशा देते हैं। आज यह संबंध पहले से कहीं अधिक गहरा और परस्पर निर्भर होता जा रहा है। “उद्योग से खेत तक” की यह यात्रा न केवल तकनीक और संसाधनों का आदान-प्रदान है, बल्कि यह प्रगति की एक मजबूत नींव का निर्माण भी है।

आधुनिक समय में उद्योगों ने कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्नत मशीनरी, बेहतर बीज, उर्वरक, सिंचाई तकनीक और कृषि उपकरणों के माध्यम से खेती अब अधिक उत्पादक और लाभकारी बन गई है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों ने किसानों की मेहनत को आसान बनाया है और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है। इससे कृषि कार्य में समय और लागत दोनों की बचत हो रही है।

कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी इस प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, डेयरी उद्योग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं ने किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद की है। अब किसान केवल कच्चा माल बेचने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे मूल्य संवर्धन (value addition) के माध्यम से अधिक लाभ कमा रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं और

नीतियों ने इस समन्वय को और मजबूत किया है। कृषि अवसंरचना कोष, पीएम-किसान योजना और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों ने खेत और उद्योग के बीच की दूरी को कम किया है। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) का विस्तार भी किसानों के लिए नए अवसर लेकर आया है।

डिजिटल तकनीक ने भी इस संबंध को और सशक्त बनाया है। अब किसान मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मौसम की जानकारी, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। वहीं उद्योग जगत भी कृषि उत्पादों की मांग और आपूर्ति को अधिक प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर पा रहा है।

इस समन्वय का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर कृषि उत्पादन बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इससे पलायन में कमी आई है और स्थानीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता बढ़ी है। ■

“उद्योग से खेत तक” की यह प्रक्रिया भारत के समग्र विकास की मजबूत नींव है। यह केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि एक ऐसा संतुलित मॉडल है जो किसानों, उद्योगों और उपभोक्ताओं—तीनों के लिए लाभकारी है। यह सहयोग और समन्वय ही भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर कर रहा है।



आत्मनिर्भर भारत की ओर विकास, रोजगार और नवाचार का संगम

आत्मनिर्भर भारत का विचार केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण है जो देश को स्वावलंबन, नवाचार और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है।

यह अभियान भारत को ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की प्रेरणा देता है, जहां संसाधनों का अधिकतम उपयोग देश के भीतर ही हो और प्रत्येक नागरिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बने।

आज भारत में विकास की गति पहले से कहीं अधिक तेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और डिजिटल क्षेत्र में हो रहे सुधारों ने देश की आर्थिक संरचना को मजबूत किया है। आधुनिक तकनीक, बेहतर कनेक्टिविटी और सरकारी नीतियों के



प्रभाव से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है और जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।

रोजगार सृजन इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत युवाओं को न केवल नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स, MSME क्षेत्र और कौशल विकास कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ा है। विशेषकर ग्रामीण और छोटे शहरों में स्थानीय उद्योगों के विस्तार से रोजगार के नए द्वार खुले हैं, जिससे पलायन में भी कमी आई है।

नवाचार इस पूरे अभियान की आत्मा है। आज भारत के युवा नई सोच, तकनीक और

रचनात्मकता के माध्यम से समस्याओं के समाधान खोज रहे हैं। डिजिटल तकनीक,

आत्मनिर्भर भारत विकास, रोजगार और नवाचार का ऐसा संगम है जो देश को एक मजबूत, सक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है। यह केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है— जहां हर कदम भारत को अधिक सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा और कृषि नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप संस्कृति ने यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने साकार किए जा सकते हैं।

सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे “मेक इन इंडिया”, “स्टार्टअप इंडिया”, “डिजिटल इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत अभियान” ने इस दिशा में मजबूत आधार प्रदान किया है। इन पहलों ने न केवल निवेश को आकर्षित किया है, बल्कि स्थानीय उत्पादन और स्वदेशी उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया है।

इस यात्रा का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर केवल सरकार के प्रयासों से नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से भी बढ़ रहा है।



किसान, युवा, उद्यमी और महिलाएं सभी इस परिवर्तन का हिस्सा बन रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति ने “वोकल फॉर लोकल” की भावना को मजबूत किया है। ■

रोजगार क्रांति

सरकारी योजनाओं से

सशक्त होता भारत



सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। लोग अब केवल नौकरी खोजने के बजाय अपने व्यवसाय शुरू करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे रोजगार सृजन का दायरा और व्यापक हो गया है।

स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी पहल ने नवाचार और उद्यमिता को नई दिशा दी है। युवा अपने विचारों को व्यवसाय में बदलकर न केवल अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। यह बदलाव भारत को एक नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में भी रोजगार क्रांति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, मत्स्य पालन और एग्री-टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए रास्ते खोले हैं। किसान अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मूल्य संवर्धन और विपणन से भी लाभ कमा रहे हैं।

महिलाओं की भागीदारी भी इस रोजगार क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और छोटे व्यवसायों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव आया है।

डिजिटल इंडिया और तकनीकी प्रगति ने रोजगार के स्वरूप को और आधुनिक बना दिया है। ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों को नए अवसर मिले हैं। यह बदलाव विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रहा है। ■

रोजगार क्रांति केवल सरकारी योजनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें सरकार, उद्योग और नागरिक सभी शामिल हैं। यह क्रांति भारत को आत्मनिर्भर, सक्षम और आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में यह बदलाव देश को और अधिक समृद्ध और अवसरों से भरपूर बनाएगा।

भा रत आज जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, उसे “रोजगार क्रांति” कहा जा सकता है। यह क्रांति केवल नौकरियों के सृजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों को आत्मनिर्भर, कुशल और उद्यमी बनाने की दिशा में एक व्यापक बदलाव है। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं ने इस परिवर्तन को मजबूत आधार प्रदान किया है, जिससे देश के करोड़ों युवाओं और श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

इस क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब रोजगार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीण और छोटे शहरों में भी रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं को विभिन्न तकनीकी और

गैर-तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया है। इससे उनकी क्षमता में वृद्धि हुई है और उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हो रहा है।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लाखों छोटे उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। छोटे व्यापार, दुकानें, सेवा क्षेत्र और ग्रामीण उद्योगों में इस योजना का

नव निर्माण की दिशा में भारत

उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि के साथ रोजगार एवं स्वरोजगार का नया युग

भा

रत आज नव निर्माण के उस चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि मिलकर विकास की एक नई, सशक्त और संतुलित तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह परिवर्तन केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को अवसर और सम्मान देने वाली एक सकारात्मक विकास यात्रा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास इस नए युग की मजबूत नींव है। आधुनिक सड़कें, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डे और डिजिटल कनेक्टिविटी ने देश को एक नई गति प्रदान की है। बेहतर परिवहन व्यवस्था ने व्यापार और आवागमन को आसान बनाया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की दूरी कम हुई है। स्मार्ट सिटी और डिजिटल सेवाओं ने जीवन को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाया है।

उद्योग क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है। “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसी पहलों ने देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है और स्थानीय उद्योगों को मजबूती दी है। छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के विस्तार से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और डिजिटल तकनीक ने भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक मजबूत स्थान दिलाया है।

कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग ने किसानों की स्थिति को बेहतर बनाया है। ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती, कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल कृषि सेवाओं ने उत्पादन और आय



नव निर्माण की दिशा में भारत का यह सफर उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि के समन्वय से एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। यह केवल विकास की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो रोजगार, स्वरोजगार और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है।

दोनों में वृद्धि की है। किसान अब केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी, मत्स्य पालन और एग्री-प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय हो रहे हैं।

इस विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू **रोजगार और स्वरोजगार का विस्तार** है। निर्माण कार्यों, उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। वहीं दूसरी ओर,

स्टार्टअप, MSME सेक्टर, फ्रीलांसिंग और डिजिटल व्यवसायों ने स्वरोजगार को नई दिशा दी है। युवा अब नौकरी खोजने के बजाय अवसर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का संकेत है।

महिलाओं की भागीदारी भी इस नए युग में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। स्वयं सहायता समूहों, छोटे व्यवसायों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और समाज में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं।

सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे कौशल विकास, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और कृषि सहायता कार्यक्रम इस परिवर्तन को गति दे रहे हैं। इन योजनाओं ने लोगों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। ■

विकसित भारत की बुनियाद टेक्सटाइल उद्योग की निर्णायक भूमिका



टेक्सटाइल उद्योग भारत के विकास की कहानी का अभिन्न हिस्सा है। यह परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु बनाकर देश को आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर सशक्त बना रहा है। यदि इस क्षेत्र में निरंतर निवेश, नवाचार और नीति समर्थन मिलता रहा, तो यह निश्चित रूप से “विकसित भारत” के विज़न को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

भा रत का टेक्सटाइल उद्योग केवल एक आर्थिक क्षेत्र नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, कौशल परंपरा और आधुनिक औद्योगिक क्षमता का अद्भुत संगम है। “विकसित भारत” के लक्ष्य को हासिल करने में यह उद्योग एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर रहा है, जो समावेशी विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा—तीनों को साथ लेकर चलता है।

सबसे पहले, टेक्सटाइल उद्योग का सबसे बड़ा योगदान है—रोजगार। यह क्षेत्र करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां सीमित अवसर होते हैं, यह उद्योग आजीविका का सशक्त माध्यम बनता है। हैंडलूम, हस्तशिल्प और छोटे कुटीर उद्योग न केवल पारंपरिक कौशल को जीवित रखते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देते हैं। महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस सेक्टर को सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि इससे आर्थिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है—आर्थिक मजबूती और निर्यात। भारत विश्व के प्रमुख टेक्सटाइल उत्पादक देशों में से एक है। कॉटन, सिल्क, जूट और रेडीमेड गारमेंट्स की वैश्विक मांग भारत को निर्यात के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करती है। विदेशी मुद्रा अर्जन के माध्यम से यह उद्योग देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता और विस्तार देता है। “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसे अभियानों ने इस क्षेत्र को और प्रोत्साहन दिया है, जिससे घरेलू उत्पादन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों में वृद्धि हुई है।

तीसरा, टेक्नोलॉजी और नवाचार का बढ़ता प्रभाव इस उद्योग को भविष्य के लिए तैयार कर

रहा है। ऑटोमेशन, स्मार्ट टेक्सटाइल, डिजिटल प्रिंटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने उत्पादन और विपणन के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इससे न केवल उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि छोटे व्यवसायों को भी वैश्विक बाजार तक पहुंचने का अवसर मिला है।

इसके अलावा, सतत विकास (Sustainability) की दिशा में भी भारतीय टेक्सटाइल उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऑर्गेनिक फैब्रिक्स, रीसाइक्लिंग और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाकर यह उद्योग “ग्रीन इकॉनमी” का हिस्सा बन रहा है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की छवि को भी सुदृढ़ करता है।

सरकारी नीतियां और योजनाएं भी इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रही हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, टेक्सटाइल पार्क, और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) जैसी पहलें उद्योग को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक हैं। इन प्रयासों से निवेश बढ़ रहा है और नए अवसर सृजित हो रहे हैं। ■

भारत में स्टार्टअप का रिकॉर्ड उछाल FY 2026 में 55,200 को मिली मान्यता



FY 26 में 55,200 स्टार्टअप्स को मिली मान्यता भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि देश के युवा केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि यही गति बनी रही, तो भारत जल्द ही वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में अग्रणी स्थान हासिल करेगा और “विकसित भारत” का सपना साकार करने में यह क्षेत्र एक निर्णायक भूमिका निभाएगा।

भा रत आज विश्व के सबसे गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक के रूप में उभर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY 26) में 55,200 से अधिक स्टार्टअप्स को आधिकारिक मान्यता मिलना इस बात का प्रमाण है कि देश में नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की भावना तेजी से मजबूत हो रही है। यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि “विकसित भारत” के विज्ञान की दिशा में एक मजबूत कदम है।

भारत में स्टार्टअप संस्कृति का विस्तार केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंच चुका है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी अपने नवाचार और विचारों के साथ उद्यमिता की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इससे न केवल क्षेत्रीय असमानता कम हो रही है, बल्कि देश के हर हिस्से में आर्थिक अवसरों का विस्तार हो रहा है।

इस रिकॉर्ड वृद्धि के पीछे सरकार की नीतियों और पहलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

“स्टार्टअप इंडिया” जैसे अभियानों ने युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, टैक्स छूट, फंडिंग सपोर्ट और मेंटरशिप जैसी सुविधाओं ने नए उद्यमों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इसके साथ ही, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने तकनीकी दक्षता और डिजिटल पहुंच को बढ़ाकर स्टार्टअप्स को मजबूती दी है।

स्टार्टअप्स का यह उभार रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर नया स्टार्टअप न केवल संस्थापकों के लिए अवसर पैदा करता है, बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के द्वार खोलता है। खासकर टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, हेल्थटेक, फिनटेक और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में नए अवसर तेजी से सामने आ रहे हैं।

नवाचार के क्षेत्र में भी भारतीय स्टार्टअप्स ने अपनी पहचान बनाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में काम कर

रहे स्टार्टअप्स न केवल घरेलू समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इससे भारत की छवि एक “इनोवेशन हब” के रूप में मजबूत हो रही है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में लगातार बढ़ रही है। महिला उद्यमी नए विचारों और नेतृत्व क्षमता के साथ इस क्षेत्र को और विविधतापूर्ण और समावेशी बना रही हैं। यह सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक सकारात्मक संकेत है। ■

एनएचएआई (NHAI) का 'आरोग्य वन' सकारात्मक बदलाव की हरित पहल

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे विकसित किए जा रहे 'आरोग्य वन' आज केवल हरियाली बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि एक बहुआयामी सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बनते जा रहे हैं। यह पहल पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज—तीनों स्तरों पर प्रभावी परिणाम दे

रही है।

सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि 'आरोग्य वन' वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक हैं। औषधीय पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं और यात्रियों को एक स्वच्छ व ताजगी भरा परिवेश प्रदान करते हैं। लंबे सफर के दौरान हरियाली से घिरे ऐसे क्षेत्र मानसिक शांति और

तनाव में कमी भी लाते हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण लाभ आयुर्वेद को बढ़ावा मिलना है। तुलसी, गिलोय, आंवला, अश्वगंधा जैसे पौधों के रोपण से लोगों में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह पहल आधुनिक जीवनशैली में प्राकृतिक उपचार को पुनः स्थापित करने का





अवसर देती है।

जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यह पहल अत्यंत लाभकारी है। स्थानीय प्रजातियों के पौधे लगाने से पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है और पक्षियों व अन्य जीवों को सुरक्षित आवास मिलता है। इससे प्राकृतिक तंत्र मजबूत होता है।

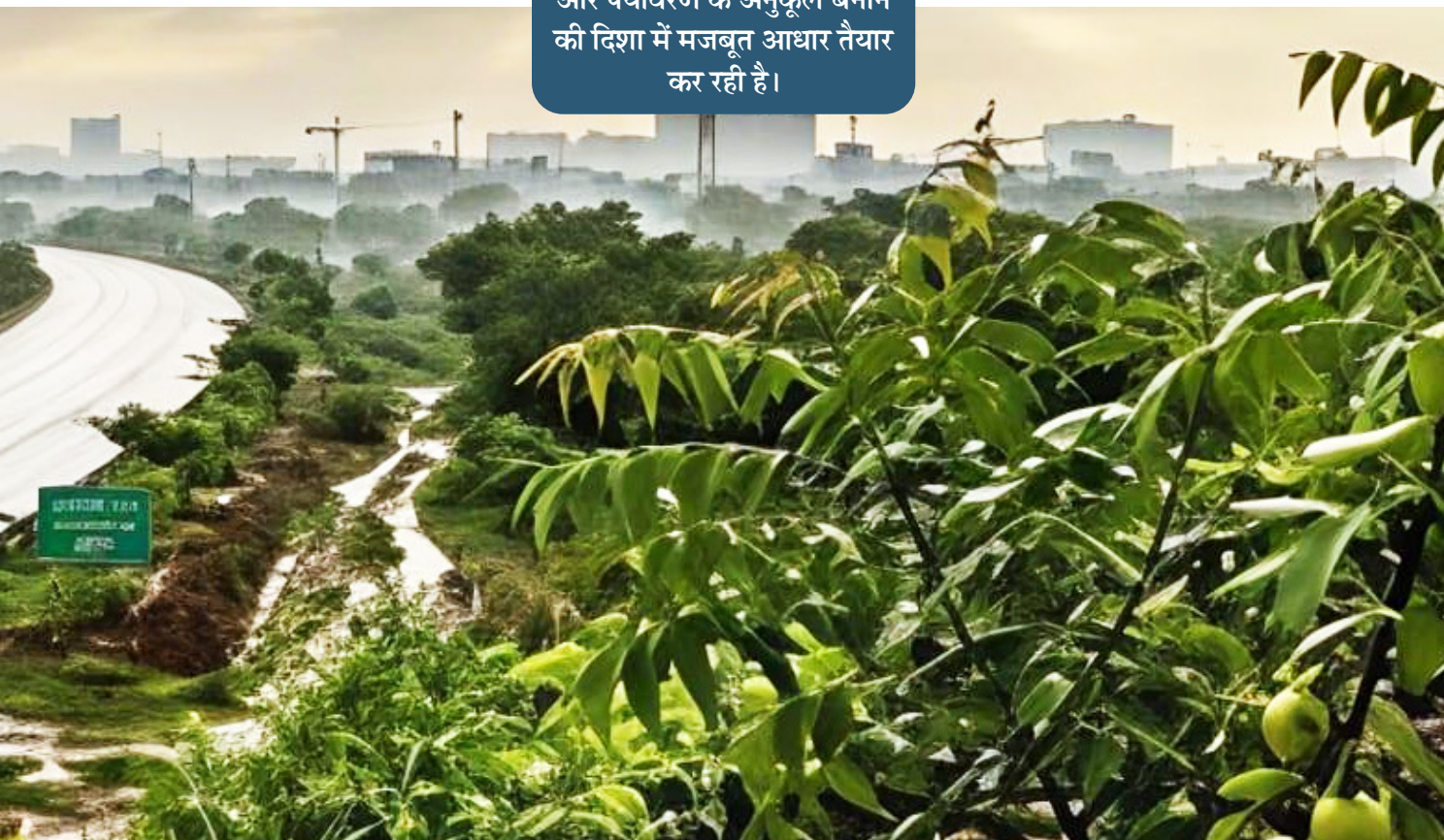
‘आरोग्य वन’ ग्रामीण और स्थानीय समुदायों

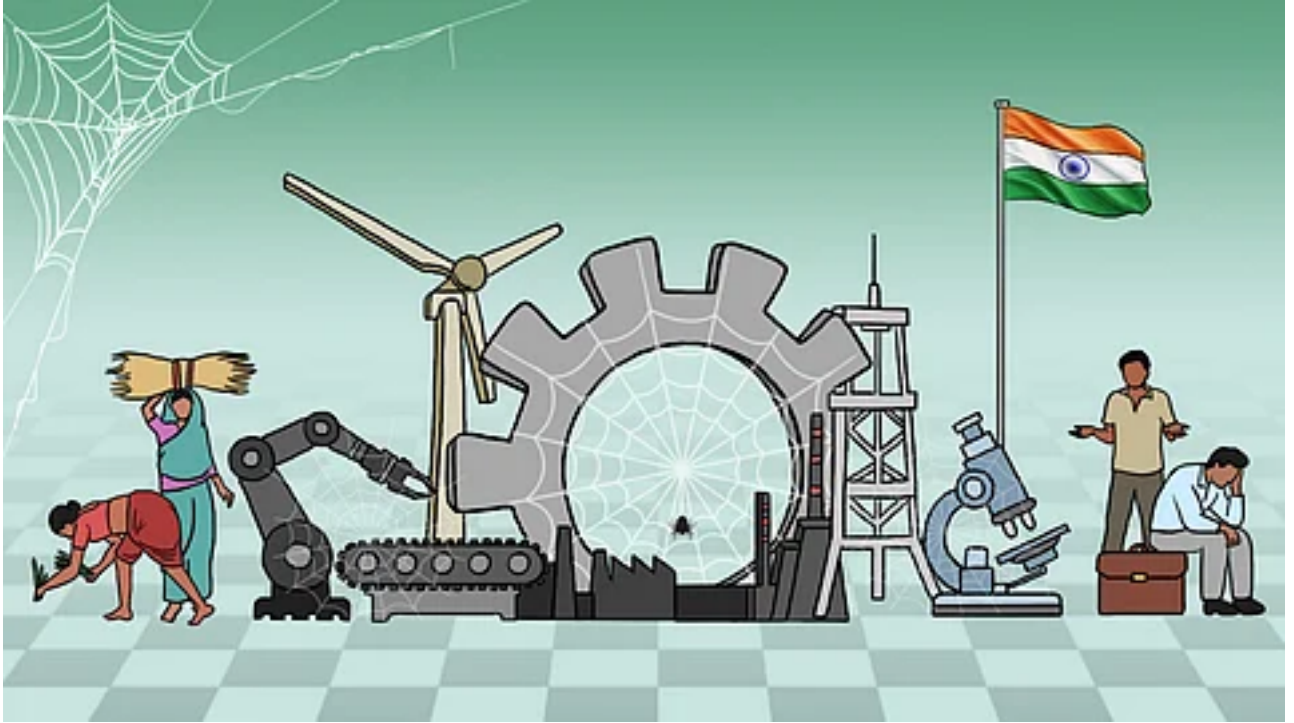
के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रहा है। पौधारोपण, देखभाल और नर्सरी प्रबंधन में

‘आरोग्य वन’ एक ऐसा प्रयास है जो हरियाली, स्वास्थ्य और समृद्धि—तीनों को साथ लेकर चलता है। यह पहल भविष्य के भारत को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार कर रही है।

लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हो रही है।

इसके अतिरिक्त, यह पहल सतत विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। यह दिखाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास केवल निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर भी किया जा सकता है। ■





दुनिया में अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनता भारत

अवसर, विश्वास और विकास की नई कहानी

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में आज भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो न केवल अपनी आंतरिक मजबूती से आगे बढ़ रहा है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता और गति प्रदान कर रहा है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों—जैसे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता—के बीच भारत ने जिस संतुलन और निरंतरता के साथ विकास की राह पकड़ी है, वह इसे एक विश्वसनीय आर्थिक आधार बनाता है।

मजबूत विकास दर और स्थिरता

भारत की अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में

उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की GDP वृद्धि दर मजबूत बनी रही है। यह संकेत देता है कि देश की आर्थिक नीतियां और संरचनाएं दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सक्षम हैं। यही कारण है कि वैश्विक निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

डिजिटल और तकनीकी परिवर्तन का नेतृत्व

भारत की डिजिटल क्रांति ने अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और स्टार्टअप संस्कृति ने देश को नवाचार का केंद्र बना दिया है। इससे न केवल व्यापार सुगम

हुआ है, बल्कि छोटे व्यवसायों और आम नागरिकों को भी आर्थिक मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिला है।

विनिर्माण और निवेश का नया केंद्र

हालिया वर्षों में 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं ने भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया है। कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां अब भारत को अपनी उत्पादन इकाइयों के लिए प्राथमिक विकल्प के रूप में देख रही हैं। इससे रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि हो रही है।



घरेलू बाजार की शक्ति

भारत का विशाल और युवा उपभोक्ता वर्ग इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बढ़ती आय, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के कारण उपभोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने में एक मजबूत कवच का काम करती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज प्रगति

सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई अड्डों के विकास में हो रहे निवेश ने भारत की आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार लागत कम हो रही है

और लॉजिस्टिक्स अधिक कुशल बन रहा है।

हरित विकास और भविष्य की दिशा

भारत नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और सतत विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह पहल न केवल पर्यावरण की रक्षा करती है, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करती है।

वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका

भारत आज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। वैश्विक

सहयोग, व्यापार समझौतों और कूटनीतिक संतुलन के माध्यम से भारत अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना रहा है। अतः आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक स्थिर, भरोसेमंद और भविष्य-उन्मुख आर्थिक शक्ति बन चुका है। हालिया वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने यह सिद्ध किया है कि सही नीतियों, नवाचार और जनशक्ति के बल पर किसी भी देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाया जा सकता है। आने वाले वर्षों में भारत की यह प्रगति न केवल देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी सकारात्मक बदलाव का संकेत है। ■

फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में PLI स्कीम: रोजगार और निवेश का नया युग



उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र में इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन (value addition) बढ़ने से किसानों की आय में भी सुधार की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला नया बल फूड प्रोसेसिंग उद्योग के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इससे न केवल रोजगार बढ़ा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर सप्लाई चेन, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में भी नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं।

निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन

इस योजना के तहत मिले इनसेंटिव ने कंपनियों को आधुनिक तकनीक अपनाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वैश्विक मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरित किया है। इससे भारतीय फूड प्रोडक्ट्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा भी मजबूत हुई है।

अतः PLI स्कीम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक परिवर्तनकारी पहल साबित हो रही है। रोजगार सृजन, निवेश वृद्धि और ग्रामीण विकास के संतुलित प्रभाव के साथ यह योजना भारत की आर्थिक संरचना को नई दिशा दे रही है। आने वाले समय में इसके और अधिक व्यापक परिणाम देखने की उम्मीद है, जो देश की विकास यात्रा को और गति प्रदान करेंगे। ■

भा

रत सरकार की प्रोडक्शन लिंकड
इंसेंटिव (PLI) योजना फूड
प्रोसेसिंग सेक्टर में तेजी से
सकारात्मक परिणाम दे रही है।

यह योजना न केवल देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ा रही है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और निवेश आकर्षण का माध्यम भी बन रही है।

हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में PLI स्कीम के तहत लगभग 3.39 लाख नए रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है। यह उपलब्धि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जहां रोजगार के सीमित अवसर होते हैं।

इसके साथ ही, इस योजना के तहत 2.1620 करोड़ (अनुमानित) का प्रोत्साहन/इनसेंटिव जारी किया गया है, जिससे उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और आपूर्ति श्रृंखला



को मजबूत करने में सहायता मिली है।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम

PLI स्कीम का उद्देश्य भारत को केवल

भारत-कोरिया औद्योगिक साझेदारी 'कोरिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप' से नए आर्थिक अवसरों का सृजन



कोरिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत और कोरिया के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक है। यह पहल निवेश, रोजगार, तकनीक और व्यापार संतुलन—चारों क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आने वाले वर्षों में यह भारत की औद्योगिक विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मजबूत निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। कोरिया के साथ यह साझेदारी दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को संतुलित करने और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगी।

निवेश और तकनीकी सहयोग में वृद्धि

कोरिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप के माध्यम से भारत में विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से उन्नत निर्माण तकनीक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में कोरियाई विशेषज्ञता भारत के औद्योगिक ढांचे को नई दिशा दे सकती है।

मेक इन इंडिया' को मजबूती

यह पहल भारत की प्रमुख योजनाओं जैसे “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” को और सशक्त बनाएगी। स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलने से आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरेगा। ■

भा

रत और दक्षिण कोरिया के बीच आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने के लिए प्रस्तावित “कोरिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप” दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा संतुलित व्यापार और निवेश सहयोग पर दिए गए जोर के साथ यह पहल भारत की औद्योगिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है।

औद्योगिक विकास का नया केंद्र

कोरिया इंडस्ट्रियल टाउनशिप का उद्देश्य भारत में कोरियाई कंपनियों के लिए एक सुव्यवस्थित औद्योगिक वातावरण तैयार करना है, जहां वे अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर सकें। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को गति मिलने की संभावना है।

रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा

इस परियोजना के माध्यम से हजारों प्रत्यक्ष

और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। साथ ही, कोरियाई तकनीक और भारतीय श्रम शक्ति के संयोजन से स्मिल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी बढ़ावा मिलेगा। यह विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा और उन्हें वैश्विक स्तर की तकनीकी दक्षता हासिल करने में मदद करेगा।

संतुलित व्यापार की दिशा में कदम

मंत्री पीयूष गोयल द्वारा संतुलित व्यापार पर दिया गया जोर यह संकेत देता है कि भारत अब केवल आयात-निर्भर बाजार नहीं, बल्कि एक



ग्रामोद्योग से आत्मनिर्भर गांव की ओर युवाओं के लिए अवसरों की नई सुबह

उ

त्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदम अब ठोस परिणामों की दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है, जो न केवल ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद लखनऊ में इस योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ब्याज सहायता युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इच्छुक युवा अपने स्वयं के उद्योग स्थापित कर सकें। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है।

इस वर्ष लखनऊ जनपद के लिए 12 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह पहल युवाओं को आत्मविश्वास, अवसर और सम्मानजनक जीवन जीने की राह दिखाती है—जहां गांव ही विकास का केंद्र बनते हैं और हर हाथ को काम मिलता है।

और समावेशी शतें हैं। सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग वर्ग के लाभार्थियों के लिए ब्याज पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह प्रावधान सामाजिक समावेशन और समान अवसर की भावना को सशक्त बनाता है।

योजना में भागीदारी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष निर्धारित की गई है, साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण रखी गई है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए मात्र 5 प्रतिशत अंशदान देना होगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें।

डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ते हुए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ सरल आवेदन प्रणाली युवाओं को बिना किसी जटिलता के योजना से जोड़ने का कार्य कर रही है। यह न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाता है, बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाओं को भी न्यूनतम करता है।

इस योजना का व्यापक प्रभाव केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन कम होगा और गांवों में ही विकास की नई धारा बहेगी। छोटे उद्योगों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिलेगी। ■

उत्तर प्रदेश: निवेश, नवाचार और निर्यात की नई उड़ान



उत्तर प्रदेश आज “ग्रोथ इंजन” बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है—जहां हर निवेश एक नए अवसर को जन्म देता है और हर पहल विकास की नई कहानी लिखती है।

उत्तर प्रदेश आज भारत के औद्योगिक मानचित्र पर तेजी से उभरते हुए एक सशक्त केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हाल ही में टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन का यह बयान कि राज्य में टाटा समूह की उपस्थिति आने वाले वर्षों में दोगुनी से अधिक हो जाएगी, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश निवेश और विकास की दृष्टि से एक नए युग में प्रवेश कर चुका है।

लखनऊ में टाटा मोटर्स की 10 लाखवीं बस के प्लैग ऑफ अवसर पर व्यक्त किए गए विचारों में उत्तर प्रदेश की अपार संभावनाओं की झलक दिखाई देती है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग-अनुकूल नीतियां और प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व ने राज्य को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर रोजगार, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

टाटा समूह का उत्तर प्रदेश में विस्तार केवल औद्योगिक वृद्धि का संकेत नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ स्थित टाटा प्लांट इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां

न केवल उत्पादन होता है, बल्कि सप्लायर्स, पार्टनर्स और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर एक मजबूत औद्योगिक नेटवर्क विकसित हुआ है। 34 वर्षों में 10 लाख वाहनों के उत्पादन का माइलस्टोन इस निरंतर प्रगति और भरोसेमंद साझेदारी का प्रतीक है।

आने वाले पांच वर्षों में 20 लाख वाहनों के उत्पादन का लक्ष्य यह दर्शाता है कि राज्य में औद्योगिक विकास की गति और तेज होने वाली है। इसके साथ ही, टाटा मोटर्स द्वारा सीएनजी, इलेक्ट्रिक और भविष्य में हाइड्रोजन आधारित वाहनों पर फोकस उत्तर प्रदेश को ग्रीन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी प्रदान करेगी।

आईटी क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की लखनऊ, नोएडा और वाराणसी

स्थित इकाइयों में वर्तमान में लगभग 20,000 प्रोफेशनल्स कार्यरत हैं, जिनकी संख्या अगले पांच वर्षों में 40,000 तक पहुंचने की संभावना है। यह वृद्धि राज्य के युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी और प्रदेश को डिजिटल और तकनीकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी।

टाटा समूह की पहलें केवल उद्योग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामाजिक विकास में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। मथुरा में जल संरक्षण, गोरखपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से समूह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। यह कॉर्पोरेट और समाज के बीच संतुलित विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

उत्तर प्रदेश का यह बदलता स्वरूप बताता है कि सही नीतियों, मजबूत नेतृत्व और निजी क्षेत्र के सहयोग से किसी भी राज्य को विकास के नए शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश न केवल देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनेगा, बल्कि निर्यात, नवाचार और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। ■



यूपी में डिजिटल गवर्नेंस की नई मिसाल 'पीएम सूर्य घर' पोर्टल से सौर ऊर्जा को मिलेगा तेज़ी का नया आयाम

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर तकनीक के माध्यम से सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) द्वारा 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पहल न केवल योजना के क्रियान्वयन को तेज़ बनाएगी, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी नई ऊंचाई देगी।

पारदर्शिता और गति का डिजिटल समाधान

नया पोर्टल www.pmsgy.upneda.co.in योजना के हर चरण—आवेदन, स्वीकृति, सोलर संयंत्र स्थापना और भुगतान—की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा देता है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों को सटीक प्रगति रिपोर्ट मिलती है, वहीं लाभार्थियों को अपने आवेदन की स्थिति जानने में आसानी होती है। यह डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम कर योजना को अधिक प्रभावी बनाता है।

डिजिटल गवर्नेंस का मजबूत उदाहरण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार 'डिजिटल गवर्नेंस' को बढ़ावा दे रही है। यह पोर्टल उसी सोच का परिणाम है, जहां तकनीक को जनसेवा का माध्यम बनाया जा रहा है। इससे सरकारी योजनाएं अधिक पारदर्शी, सुलभ और समयबद्ध बन रही हैं।

केंद्र सरकार की सराहना

इस मॉडल की सफलता का अंदाजा इसी

'पीएम सूर्य घर' पोर्टल केवल एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि सुशासन का एक सशक्त माध्यम है। यह पहल दर्शाती है कि सही नीति, मजबूत नेतृत्व और तकनीक के समन्वय से बड़े बदलाव संभव हैं। उत्तर प्रदेश का यह मॉडल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।

बात से लगाया जा सकता है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भी इसकी सराहना की है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह का पोर्टल विकसित करने के लिए यूपीनेडा से तकनीकी सहयोग मांगा है। यह उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है और राज्य की नवाचार क्षमता को दर्शाता है।

सौर ऊर्जा में ऐतिहासिक उपलब्धि

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में अब तक 4.80 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह उपलब्धि न केवल प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करती है, बल्कि स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।

हर घर सोलर का सपना

सरकार का लक्ष्य 'हर घर सोलर' की परिकल्पना को साकार करना है। इस पहल से आम नागरिकों को बिजली बिल में राहत मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। ■



यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 नवाचार, उद्यमिता और वैश्विक अवसरों का संगम

उत्तर प्रदेश एक बार फिर वैश्विक व्यापार मानचित्र पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। आगामी 25 से 29 सितम्बर 2026 के बीच आयोजित होने वाला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 इस बार नए विज्ञान, विस्तृत दायरे और बड़े लक्ष्यों के साथ सामने आएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य इसे केवल एक प्रदर्शनी तक सीमित न रखकर एक प्रभावी ग्लोबल सोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आयोजित तैयारियों की समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि इस वर्ष का फोकस “जनता तक उपलब्धियों का प्रभावी संप्रेषण” रहेगा। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों को आकर्षक एवं विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आमजन और निवेशकों के बीच

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति, नवाचार क्षमता और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बनने जा रहा है। यह मंच प्रदेश को “मेक इन इंडिया” और “लोकल टू ग्लोबल” की दिशा में एक नई गति प्रदान करेगा।

बेहतर संवाद स्थापित हो सके।

इस बार ट्रेड शो में डेयरी, उद्योग, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में नवाचार आधारित व्यावसायिक मॉडल मुख्य आकर्षण होंगे। ये सेक्टर न केवल प्रदेश की आर्थिक रीढ़ हैं, बल्कि युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलते हैं। आधुनिक तकनीक, वैल्यू

एडिशन और स्टार्टअप आधारित दृष्टिकोण इस आयोजन को और अधिक प्रासंगिक बनाएंगे।

निजी क्षेत्र और छोटे कॉर्पोरेट्स की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्टॉल आवंटन और शुल्क संरचना को संतुलित रखा गया है। 7,500 से 8,000 रुपये के बीच निर्धारित दरें छोटे उद्यमियों को भी मंच प्रदान करेंगी, जबकि विशेष प्रकार के स्टॉल के लिए अतिरिक्त शुल्क का प्रावधान पारदर्शिता को बनाए रखेगा।

युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए “सीएम युवा” पवेलियन को इस बार और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। यह मंच खासकर एनसीआर और गौतम बुद्ध नगर के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। नवाचार, नेटवर्किंग और निवेश के अवसरों का यह संगम युवाओं के सपनों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ■

भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत बढ़त की उम्मीद WTC के संकेतों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में जिस गति से वैश्विक चुनौतियों के बीच आगे बढ़ रही है, वह न केवल निवेशकों के लिए आश्वस्त करने वाली है, बल्कि आने वाले महीनों में बाजारों के लिए भी मजबूत आधार तैयार कर रही है। हाल ही में World Trade Council (WTC) से जुड़े विश्लेषणों और बाजार रुझानों के अनुसार, 1 मई के बाद भारतीय शेयर बाजारों में और अधिक स्थिरता एवं तेजी देखने की संभावना जताई जा रही है।

मजबूत आर्थिक संकेतकों से बढ़ा भरोसा भारत की GDP वृद्धि दर, नियंत्रित मुद्रास्फीति, और लगातार बढ़ता घरेलू उपभोग—ये सभी संकेतक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में आई तेजी ने निवेशकों के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया है।

इसके अलावा, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का लगातार बढ़ता

निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूती

जहां एक ओर वैश्विक बाजारों में अस्थिरता

भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत संरचनात्मक विकास चरण में प्रवेश कर चुकी है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की आंतरिक मजबूती, नीतिगत समर्थन और निवेश प्रवाह इसे निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। 1 मई के बाद बाजारों में संभावित तेजी इस सकारात्मक यात्रा को और गति दे सकती है। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए केवल वृद्धि का नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और वैश्विक नेतृत्व की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा सकता है।

और भू-राजनीतिक तनाव देखने को मिल रहे हैं, वहीं भारत अपेक्षाकृत स्थिर आर्थिक प्रदर्शन कर रहा है। यह स्थिति विदेशी निवेशकों के लिए भारत को एक आकर्षक गंतव्य बना रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि भारत की आंतरिक मांग आधारित अर्थव्यवस्था इसे वैश्विक झटकों से कुछ हद तक सुरक्षित रखती है। यही कारण है कि बाजारों में गिरावट के बाद भी तेजी से रिकवरी देखने को मिल रही है।

1 मई के बाद संभावित बाजार रुझान

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, 1 मई के बाद कॉरपोरेट अर्निंग्स में सुधार और नीति स्तर पर संभावित सकारात्मक घोषणाओं के चलते बाजार में नई तेजी आ सकती है। बैंकिंग, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इस वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही, खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और म्यूचुअल फंड्स में लगातार बढ़ता निवेश भी बाजार को मजबूती प्रदान कर रहा है।

निवेशकों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दीर्घकालिक निवेशकों के लिए भारतीय बाजार आकर्षक अवसर प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि अल्पकालिक उतार-चढ़ाव बने रह सकते हैं, लेकिन समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेशकों को गुणवत्तापूर्ण कंपनियों में धैर्यपूर्वक निवेश बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में आर्थिक विकास की गति और तेज होने की संभावना है। ■





आधी आबादी को नई उड़ान गन्ना समितियों में महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गन्ना समितियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह (SHGs) की महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का अभिनव निर्णय लिया है। यह पहल न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

निशुल्क स्थान: आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी

सरकार द्वारा गन्ना सहकारी समितियों के परिसरों में उपलब्ध खाली स्थान महिलाओं को 'प्रेरणा कैटीन' और मार्केटिंग/डिस्प्ले सेंटर स्थापित करने के लिए निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि शुरुआती दो वर्षों तक इन स्थानों के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इसके बाद भी महिलाओं को केवल 50

प्रतिशत किराया देना होगा, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम रहेगा और वे अपने व्यवसाय को मजबूती से स्थापित कर सकेंगी।

स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार

इस योजना के तहत महिलाएं अपने हस्तनिर्मित उत्पादों, घरेलू वस्तुओं, खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और सोलर लैंप जैसे नवाचार उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। इससे जहां उनकी आय में वृद्धि होगी, वहीं स्थानीय उत्पादों को भी एक संगठित और स्थायी बाजार मिलेगा। यह पहल 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को भी सशक्त करती है।

प्रशिक्षण और समर्थन: सफलता की कुंजी

महिलाओं को केवल स्थान ही नहीं, बल्कि व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसमें कैटीन संचालन, साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण

यह पहल केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि महिलाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी समाज और राष्ट्र सशक्त होगा। गन्ना समितियों के माध्यम से शुरू की गई यह पहल निश्चित ही उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी और महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई पहचान देगी।

और विपणन कौशल शामिल हैं। विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके उत्पादों की पहचान और मांग दोनों बढ़ेंगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा संबल

यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन और खपत के चक्र को मजबूत करेगी। जब स्थानीय स्तर पर उत्पाद बनेंगे और बिकेंगे, तो इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। गन्ना समितियां, जो अब तक केवल कृषि से जुड़ी थीं, अब बहुआयामी विकास के केंद्र बन सकेंगी।

सरकार और समाज का साझा प्रयास

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महिलाओं को हर स्तर पर सहयोग मिले और वे आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ा सकें। ■



महिला सशक्तीकरण की नई इबारत उत्तर प्रदेश में बदलाव की कहानी

उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के सशक्तीकरण को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य किए गए हैं। सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी है। विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में ठोस प्रयास देखने को मिले हैं।

सबसे उल्लेखनीय पहल महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ना रहा है। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा है। एक करोड़ से अधिक महिलाओं को इन समूहों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसी क्रम में “लखपति दीदी” जैसी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया है।

बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” और “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” जैसी पहलें बेहद प्रभावशाली रही हैं। इन योजनाओं

जब योजनाएं सही दिशा में और प्रभावी ढंग से लागू की जाती हैं, तो उनका सकारात्मक प्रभाव समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तीकरण की यह यात्रा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी तैयार कर रही है।

ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी मजबूती दी है। इसके साथ ही “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाकर शिक्षा और समानता का संदेश फैलाया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में “बीसी सखी योजना” ने महिलाओं को वित्तीय सेवाओं से जोड़ते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां दी हैं। इसके माध्यम से महिलाओं ने बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन को संभाला है, जिससे उनके कौशल और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है। इसी तरह “विद्युत सखी”

पहल ने भी महिलाओं को नई पहचान दी है और उन्हें आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतिगत बदलाव भी किए गए हैं। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देना एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिससे उन्हें अपने करियर विकल्पों का विस्तार करने का अवसर मिला है। सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयासों ने इस पहल को और प्रभावी बनाया है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए गए हैं। निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन राशि में वृद्धि और पोषण योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे समाज के कमजोर वर्गों को स्थिरता और सुरक्षा का अहसास हुआ है।

महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हेल्पलाइन सेवाओं और सहायता कोष जैसी व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। इससे संकट की स्थिति में महिलाओं को त्वरित सहायता और न्याय मिलना संभव हुआ है। ■



स्वदेशी, संस्कृति और संभावनाओं का संगम रांची में आयोजित “सांसद सांस्कृतिक महोत्सव-सह-स्वदेशी मेला-2026”

रांची के ऐतिहासिक आँड़े हाउस परिसर में आयोजित तीन दिवसीय “सांसद सांस्कृतिक महोत्सव-सह-स्वदेशी मेला-2026” न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन था, बल्कि यह स्वदेशी भावना, स्थानीय प्रतिभाओं और झारखंड की समृद्ध विरासत को एक मंच पर लाने का प्रेरणादायक प्रयास भी रहा। इस महोत्सव का उद्घाटन संतोष कुमार गंगवार और हेमन्त सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ, जिसने आयोजन की महत्ता को और भी बढ़ा दिया।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अपने संबोधन में स्वदेशी उत्पादों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वदेशी केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मनिर्भरता, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए बताया कि स्वदेशी अपना रास्ते निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मेला स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और उद्यमियों के लिए एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जहां वे अपने हुनर को प्रदर्शित कर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

झारखंड, जिसे प्रायः खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है, अपनी सांस्कृतिक विविधता

“सांसद सांस्कृतिक महोत्सव-सह-स्वदेशी मेला-2026” केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक सकारात्मक पहल है, जो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह मेला झारखंड की पहचान, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।

और कलात्मक समृद्धि में भी उतना ही समृद्ध है। इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया कि राज्य सरकार केवल प्राकृतिक संसाधनों तक ही सीमित नहीं, बल्कि यहां की कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी प्रतिबद्ध है। पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी ने आगंतुकों को झारखंड की जीवंत

सांस्कृतिक झलक प्रदान की।

मेले में प्रदर्शित हस्तनिर्मित वस्त्र, आभूषण, मिट्टी एवं बांस से बने उत्पाद और घरेलू सजावटी सामग्री स्थानीय कारीगरों की सृजनात्मकता और कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण थे। इन उत्पादों में न केवल सौंदर्य था, बल्कि उनमें स्थानीय परंपराओं और जीवनशैली की झलक भी समाहित थी। यह पहल “वोकल फॉर लोकल” के विचार को सशक्त रूप से आगे बढ़ाती है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होती है।

मुख्यमंत्री ने झारखंड के युवाओं की प्रतिभा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य के बच्चे और युवा शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि यदि उचित अवसर और मंच मिलें, तो झारखंड की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं।

इस आयोजन में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, कलाकारों और प्रबुद्धजनों की उपस्थिति ने इसे और अधिक समृद्ध बनाया। लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक नृत्य और गीतों ने पूरे वातावरण को जीवंत कर दिया, जिससे यह महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में स्थापित हुआ। ■

समृद्ध उद्योग – सशक्त बिहार : औद्योगिक प्रगति की नई उड़ान (वित्तीय वर्ष 2025-26)



बिहार आज औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक नई पहचान गढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व तथा उद्योग मंत्री डॉ.

दिलीप कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उद्योग विभाग की सक्रिय नीतियों, निवेशक-अनुकूल वातावरण और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे ने बिहार को पूर्वी भारत के उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

राज्य सरकार ने “समृद्ध उद्योग – सशक्त बिहार” के विजन के तहत अगले पाँच वर्षों में 50 लाख करोड़ निवेश आकर्षित करने और 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और शहरी अवसंरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे उद्योगों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो रहा है।

निवेश और नीतिगत मजबूती

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को 747

वित्तीय वर्ष 2025-26 बिहार के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो रहा है। नीतिगत स्थिरता, निवेशक विश्वास और समावेशी विकास के साथ बिहार तेजी से औद्योगिक प्रगति की ओर अग्रसर है। यदि यही गति बनी रही, तो आने वाले वर्षों में बिहार न केवल पूर्वी भारत बल्कि पूरे देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा।

निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 17,000 करोड़ से अधिक निवेश की संभावना है। BIIPP 2025 जैसे प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से निवेशकों को भूमि, पूंजी अनुदान, ब्याज सहायता और कर लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही, सेमीकंडक्टर नीति 2026 के लागू होने से बिहार तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में अग्रसर है।

औद्योगिक अवसंरचना का विस्तार

गया में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग सिटी, मुजफ्फरपुर में टेक्सटाइल इकाइयाँ,

दामोदरपुर में मेगा फूड पार्क तथा विभिन्न जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राज्य की औद्योगिक क्षमता को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहा है। फतुहा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और प्रस्तावित फिनटेक सिटी आधुनिक उद्योगों को आकर्षित करने में सहायक होंगे।

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार

निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बिहार को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा गया है। श्रम कानूनों में सुधार, महिलाओं के कार्य समय में लचीलापन और औद्योगिक संचालन को सरल बनाने वाले कदम राज्य को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना रहे हैं।

स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा

स्टार्टअप बिहार के तहत 1,600 से अधिक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया है, जिनमें बड़ी संख्या महिला उद्यमियों की है। इनक्यूबेशन सेंटर, को-वर्किंग स्पेस और IIT पटना के सहयोग से स्थापित जीरो लैब नवाचार को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से हजारों युवाओं को वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक उद्योग

हस्तकरघा, रेशम, खादी और ग्रामोद्योग जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बुनकरों को आर्थिक सहायता, खादी मॉल की बढ़ती बिक्री और मधुबनी पेंटिंग जैसे पारंपरिक शिल्पों को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

वैश्विक पहचान की ओर बिहार

देश-विदेश में आयोजित निवेशक रोड शो और उद्योग सम्मेलनों के माध्यम से बिहार ने वैश्विक निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। बिहार फाउंडेशन के विस्तार से प्रवासी बिहारी समुदाय भी राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ■



उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन आत्मनिर्भरता, पर्यावरण और ग्रामीण समृद्धि की नई दिशा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद उत्पादन की प्रक्रिया का अवलोकन करना राज्य में एक सकारात्मक और दूरदर्शी पहल का संकेत है। मात्र 45 दिनों में 520 किलोग्राम शहद का उत्पादन इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा और संसाधन मिलें, तो मधुमक्खी पालन राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शहद उत्पादन: संभावनाओं का विस्तृत आकाश

उत्तराखंड के पर्वतीय और वन क्षेत्रों में जैव विविधता की प्रचुरता है, जो मधुमक्खी पालन के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। मुख्यमंत्री द्वारा बी-बॉक्स स्थापित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने के निर्देश इस क्षेत्र में संगठित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने की यह पहल बहुआयामी लाभ प्रदान करने वाली है। यह न केवल रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और ग्रामीण विकास को भी नई गति देगी। यदि इस दिशा में योजनाबद्ध और सतत प्रयास जारी रहे, तो उत्तराखंड शहद उत्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बन सकता है।

स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को प्राथमिकता देने का निर्णय युवाओं और किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। इस क्षेत्र में विशेष सब्सिडी की व्यवस्था न केवल लोगों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी अग्रसर करेगी।

मधुमक्खी पालन कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आदर्श विकल्प बन सकता है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास

“श्री-बी” (बर्ड फ्रेंडली, बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली) गार्डन की परिकल्पना पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अभिनव पहल है। इस प्रकार के उद्यान न केवल परागण को बढ़ाते हैं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस और हरेला पर्व जैसे अवसरों पर इस तरह के पौधारोपण अभियान जनभागीदारी को भी बढ़ावा देंगे।

स्थायी विकास की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री द्वारा वर्षभर शहद उत्पादन के लिए उपयुक्त पौधों के रोपण पर बल देना दीर्घकालिक योजना का संकेत है। इससे न केवल उत्पादन निरंतर बना रहेगा, बल्कि किसानों की आय में स्थिरता भी आएगी। यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूत करेगी। ■



स्टार्टअप सेक्टर में 10,000 करोड़ का FoP निवेश को मिलेगा नया बल, विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद

10,000 करोड़ रुपये का यह FoP न केवल एक वित्तीय पहल है, बल्कि यह भारत के स्टार्टअप भविष्य को नई दिशा देने वाला रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है। आने वाले महीनों में इसका असर निवेश, नवाचार और रोजगार के आंकड़ों में स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है।

दे

श के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। 10,000 करोड़ रुपये के FoP (Fund of Platform/Programme) पहल को स्टार्टअप सेक्टर में एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि नवाचार और रोजगार सृजन को भी नई गति देगा।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य उभरते स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण से लेकर विस्तार (scale-up) तक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है। छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों के लिए यह फंड एक मजबूत सहारा साबित हो सकता है, जिससे उन्हें पूंजी की कमी जैसी प्रमुख चुनौतियों से राहत मिलेगी।

निवेश माहौल में सुधार की उम्मीद

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के बड़े फंड से घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

विशेषकर टेक्नोलॉजी, फिनटेक, एग्रीटेक और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नए निवेश के अवसर खुल सकते हैं।

स्टार्टअप फाउंडर्स के अनुसार, यह पहल नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ जोखिम लेने की क्षमता को भी मजबूत करेगी, जिससे नए विचारों को तेजी से बाजार में उतारा जा सकेगा।

रोजगार और नवाचार को बढ़ावा

इस फंड के जरिए हजारों नए रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है। साथ ही, ग्रामीण और टियर-2 शहरों में भी स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इससे आर्थिक विकास का दायरा और अधिक व्यापक होने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों की राय

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस फंड का प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया गया, तो यह भारत को वैश्विक स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ■



भारत की ऊर्जा क्रांति में सौर शक्ति का स्वर्णिम उदय

भारत ने हाल ही में 256 गीगावाट (GW) के रिकॉर्ड बिजली मांग स्तर को पार कर एक नया इतिहास रचा है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के पीछे यदि किसी एक ऊर्जा स्रोत की सबसे बड़ी भूमिका रही है, तो वह है—सौर ऊर्जा। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और हरित भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

सौर ऊर्जा: बढ़ती मांग का मजबूत सहारा

तेजी से बढ़ती बिजली की मांग के इस दौर में सौर ऊर्जा ने न केवल आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में मदद की है, बल्कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी कम की है। दिन के समय, जब बिजली की खपत अपने चरम पर होती है, सोलर पावर प्लांट्स बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन कर ग्रिड को संतुलित बनाए रखते हैं।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

सौर ऊर्जा पूरी तरह स्वच्छ और नवीकरणीय

है। इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने में मदद मिलती है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जहां औद्योगिक विकास भी जरूरी है और पर्यावरण संरक्षण भी, सौर ऊर्जा एक संतुलित समाधान बनकर उभरी है।

आर्थिक और सामाजिक लाभ

सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार से न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ा है, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार और ऊर्जा पहुंच दोनों में सुधार हुआ है।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

घरों की छतों पर सोलर पैनल (रूफटॉप सोलर) की बढ़ती लोकप्रियता ने आम नागरिकों को भी ऊर्जा उत्पादक बना दिया है। इससे बिजली बिल में कमी के साथ-साथ ऊर्जा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है।

256 गीगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग को पूरा करने में सौर ऊर्जा की निर्णायक भूमिका यह साबित करती है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह केवल ऊर्जा उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि एक हरित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की नींव है। आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा भारत की विकास गाथा का सबसे उज्ज्वल अध्याय बनने जा रही है।

सरकार की सक्रिय पहल

सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं—जैसे सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर सब्सिडी और उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं—इस क्षेत्र को गति देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। “राष्ट्रीय सौर मिशन” जैसे कार्यक्रमों ने भारत को वैश्विक सौर ऊर्जा मानचित्र पर एक अग्रणी देश बना दिया है।

वैश्विक नेतृत्व की ओर भारत

आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग कर रहे हैं। यह न केवल ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि भारत को वैश्विक जलवायु नेतृत्व में भी आगे लाता है। ■



महिलाओं की रोजगार दर में ऐतिहासिक वृद्धि आत्मनिर्भर भारत की और मजबूत कदम

भारत में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को लेकर एक बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार, वर्ष 2017 में जहां महिलाओं की रोजगार दर मात्र 22% थी, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 39% हो गई है। यह वृद्धि न केवल आंकड़ों में सुधार को दर्शाती है, बल्कि समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका और बढ़ते आत्मविश्वास का भी प्रमाण है।

इस प्रगति के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं—जैसे

कौशल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार को बढ़ावा, और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन—ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वर्क-फ्रॉम-होम जैसी सुविधाओं ने भी महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के माध्यम से महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार और सामाजिक सोच में बदलाव ने भी महिलाओं को घर की चारदीवारी

आने वाले समय में यदि यही रफ्तार बनी रही, तो भारत न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने में एक वैश्विक उदाहरण बनेगा, बल्कि एक संतुलित और सशक्त समाज की दिशा में भी तेजी से अग्रसर होगा।

से बाहर निकलकर अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया है।

महिलाओं की रोजगार दर में यह वृद्धि भारत की समावेशी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह न केवल लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को भी नई गति प्रदान करता है। ■



MGNREGA के तहत श्रमिकों के e-KYC वेरिफिकेशन में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर

छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर सुशासन और तकनीकी नवाचार का उदाहरण पेश करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत श्रमिकों के e-KYC वेरिफिकेशन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में किए गए सतत प्रयासों का परिणाम है।

राज्य में श्रमिकों के e-KYC सत्यापन को तेज और प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया। इसके

तहत आधार-आधारित प्रमाणीकरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रमिकों की पहचान सुनिश्चित की गई, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगी और वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा। इस प्रक्रिया ने न केवल पारदर्शिता बढ़ाई, बल्कि भुगतान प्रणाली को भी अधिक सुगम और विश्वसनीय बनाया।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान चलाकर श्रमिकों को e-KYC प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके

छत्तीसगढ़ का यह कदम डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मजबूत पहल है, जो यह दर्शाता है कि सही नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन से प्रशासनिक सुधार संभव है।

परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में श्रमिकों ने समय पर अपना सत्यापन पूरा किया।

इस उपलब्धि का सीधा लाभ राज्य के ग्रामीण श्रमिकों को मिल रहा है। समय पर मजदूरी भुगतान, योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी जैसे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। साथ ही, यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरी है। ■

गंगा एक्सप्रेसवे—नए उत्तर प्रदेश की विकासधारा

उत्तर प्रदेश ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ प्रदेश के विकास को नई दिशा मिली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इसे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक परिवर्तन की “नई लाइफलाइन” बताया।

गंगा एक्सप्रेसवे आज “नए उत्तर प्रदेश” की पहचान बनकर उभर रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, वह अभूतपूर्व है। एक्सप्रेसवे ने न केवल शहरों को जोड़ा है, बल्कि गांवों, किसानों और स्थानीय उद्योगों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है।

इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ किसानों और छोटे उद्यमियों को मिलेगा। अब फसलें और स्थानीय उत्पाद—जैसे मेरठ के स्पोर्ट्स गुड्स, हरदोई का हैंडलूम, उन्नाव का लेदर और प्रतापगढ़ का आंवला—तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगे। इससे आय में वृद्धि और स्थानीय उद्योगों को नई पहचान मिलने की संभावना है। साथ ही, एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक विकास से युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

गंगा एक्सप्रेसवे की एक और विशेषता इसका भविष्य दृष्टिकोण है। इसे आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है, जिससे यह धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण बन जाएगा। साथ

गंगा एक्सप्रेसवे इस बदलाव का प्रतीक है—एक ऐसा मार्ग जो केवल दूरी कम नहीं करता, बल्कि संभावनाओं को करीब लाता है। यह परियोजना दर्शाती है कि जब दूरदृष्टि और प्रभावी नेतृत्व साथ होते हैं, तो विकास की रफ्तार सचमुच एक्सप्रेसवे से भी तेज हो सकती है।

ही, इसे अन्य एक्सप्रेसवे से जोड़कर एक सशक्त नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डिफेंस मैनुफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र भी इस परिवर्तन के प्रमुख आधार हैं। उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है और 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ■



गंगा एक्सप्रेस-वे

- कुल लंबाई
594 किलोमीटर
- लेन की संख्या
6 लेन (भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है)
- कुल लागत
लगभग ₹36,230 करोड़ (जमीन अधिग्रहण सहित)
- डिजाइन स्पीड
120 किमी/घंटा (निर्धारित गति 100-120 किमी/घंटा)
- शुरुआत और अंत
मेरठ (खिजौली गांव) से प्रयागराज (जुदापुर डंडू गांव)



इफको नैनो उर्वरक अपनाएं अधिक उपज और गुणवत्ता पाएं इफको की असरदार जोड़ी

नैनो
यूरिया
प्लस

नैनो
डीएपी

नैनो जिंक

नैनो कॉपर



अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री न. 1800-103-1967
www.iffco.in | www.nanourea.in | www.nanodap.in



आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के



सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा वय वंदना योजना का लाभ

योजना की विशेषताएं

- सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार
- मौजूदा बीमारियों का कवरेज पहले दिन से लागू
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, जिनके पास पहले से कोई निजी बीमा है, वे भी पात्र होंगे
- 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के राज्य बीमा योजना (ESIC) के लाभार्थी भी पात्र होंगे



कैसे बनवाएं आयुष्मान वय वंदना कार्ड?

प्ले स्टोर से
आयुष्मान ऐप
डाउनलोड करें

मोबाइल नंबर से
लॉगिन करें

सभी आवश्यक
जानकारी भरें
और e-KYC करें

अपना कार्ड
डाउनलोड करें

आवश्यक दस्तावेज



आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर

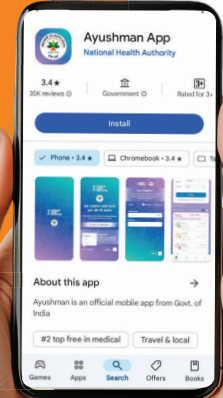
पात्रता के मापदंड



लाभार्थी की आयु 70 वर्ष या
उससे अधिक होना अनिवार्य है



आयु का सत्यापन आधार
e-KYC के माध्यम से ही पूरा होगा



आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत

15 जनवरी से 15 अप्रैल, 2026 तक विशेष अभियान

इस दौरान अपने नजदीकी कैंप पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं

सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची जानने के लिए QR कोड स्कैन करें



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : 1800-1800-4444/14555

कार्यालय का पता

दूसरी और चौथी मंजिल, नवचेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

अब इंटरनेट किस बात का,
आज ही ऐप डाउनलोड कर बनवाएं

आयुष्मान वय वंदना कार्ड



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial

CMOUttarpradesh

CMOfficeUP